देश का कॉर्पोरेट जगत नहीं है हर मर्ज की दवा



वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बड़े कारोबारी सम्मेलन में भारत में खपत के बारे में एक महत्वपूर्ण बात कही कि आने वाले समय में खपत बढ़ाने वाली ताकतें वास्तव में लोगों की आर्थिक तरक्की और आय में बढ़ोतरी करेंगी। आइए, इस बात की थोड़ी जाँच-पड़ताल करते हैं–

- आमदनी बढ़ने पर अलग-अलग क्षेत्रों में भी खर्च करने वालों की संख्या बहुत है; जैसे–कृषक, निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले, परिवहन से जुड़े लोग व छोटे-मोटे कारोबारी। वित्त मंत्री ने कॉर्पोरेट इंडिया से उभरते बाजार को ध्यान में रखकर कार्य करने की अपील की पर क्या कुछ अमीरों की बढ़ती आय का फायदा करोड़ों आम लोगों की आय में होने वाली छोटी-सी वृद्धि से नहीं मिल सकता?
- आय में वृद्धि होने पर जिन क्षेत्रों में लोग खर्च करते हैं, वह बाजार पहले से ही छोटे और क्षेत्रीय कारोबारियों से भरा हुआ है। पर नीतियाँ बनाने वाले आज भी संगठित व असंगठित की पुरानी छवि में उलझे हुए हैं।
- आज डिजिटल तकनीक से छोटे कारोबारी भी बड़े बाजार तक पहुँच बना रहे हैं। उनके लिए जरूरी जानकारी हासिल करना तथा बड़ी प्रतिभाओं से जुड़ना आसान हुआ है। पर वित्त एक समस्या आज भी है। आज इन्ही कारणों से छोटे उद्यमी भी बेहतर उत्पाद देने लगे हैं, जो अमेज़न पर भी हम देख सकते हैं। साथ ही वे किफायती भी होते हैं। इसलिए लोग आय बढ़ने के बाद भी उत्पादों को छोड़ना नहीं चाहते।
- आज बहुत सारे सामान जब सस्ते दामों में चीन से भारत आते हैं, तो लोग उनका भी खूब प्रयोग करते हैं।
- आज तक कम आय वाले उपभोक्ताओं की ज्यादातर जरूरतें छोटे कारोबारी पूरा करते हैं और बड़ी कंपनियाँ बड़े उपभोक्ताओं की जरूरतों पर ध्यान देती हैं।

सिर्फ बड़े उपभोक्ताओं को आर्थिक वृद्धि का आधार मानने पर चिंताएँ -

- सरकारी आँकड़ों के अनुसार पिछले दशक में बड़े उपभोक्ता वर्ग की जरुरी खर्च के बाद बचने वाली आय में वृद्धि बहुत कम रही है। पर अधिक आय वाले छोटे से वर्ग की यह संख्या तेजी से बढ़ी है। छोटी आय वाले बड़े उपभोक्ता वर्ग को नीतियों में नजरअंदाज करना क्या सही है या दूरदर्शिता की कमी?
- आज एकल परिवार बढ़ रहे हैं। घर भी इस कारण ज्यादा बन रहे हैं। तो कॉर्पोरेट जगत इस पर ध्यान दे सकता है।
- आज छोटे कारोबारियों को MSME, स्टार्टअप उद्योग तथा अनौपचारिक उद्यम में बाँटकर देखा जाता है। इसलिए नीतियाँ बनाने का दृष्टिकोण भी खंडित हो जाता है।

आगे की राह -

- नीति-निर्माताओं को भारत के उपभोक्ताओं, आपूर्तिकर्ताओं और रोजगार देने वाले कारोबारियों की इस बहुस्तरीय संरचना को समग्र रूप से देखना चाहिए और उसी के अनुसार अलग-अलग स्तर की स्पष्ट विभाजन नीतियाँ बनानी चाहिए।
- देश की बड़ी कंपनियों को अपने कर्मचारियों के साथ लाभ का एक न्यायपूर्ण हिस्सा साझा करना चाहिए, इससे लोगों की आय बढ़ेगी।
- अनौपचारिक क्षेत्र की मजदूरी या सरकारी कर्मचारियों की आय का श्रम बाजार पर वैसा संकेतिक प्रभाव नहीं पड़ता, जैसा मनरेगा जैसी योजना के तहत मिलने वाली मजदूरी का पड़ता है।

हमें आर्थिक विकास के पुराने सिद्धांतों पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है।

*****